टीबी मरीजों में गिरावट समर्पित प्रयासों का परिणाम : मोदी

नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को टीबी के मामलों को कम करने में देश की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बीमारी में गिरावट भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी.नड्डा के एक पोस्ट का जवाब दिया। उन्होंने कहा, "सराहनीय प्रगति। सामूहिक भावना के साथ हम टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करते रहेंगे।"

स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने पोस्ट किया था कि हम टीबी मुक्त भारत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत की उल्लेखनीय प्रगति को मान्यता दी है। वर्ष 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में 17.7 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो वैश्विक स्तर 8.3 फीसदी की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। यह स्वीकृति भारत के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, 30 उच्च टीबी-बोझ वाले देशों में से भारत में टीबी के लिए उपचार कवरेज का स्तर उच्चतम है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में टीबी रोगियों और एचआइवी से पीड़ित लोगों के घरेलू संपर्कों के लिए निवारक चिकित्सा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। भारत में 2023 में 12.2 लाख लोगों को निवारक चिकित्सा पर रखा गया, जो 2022 में 10.2 लाख और 2021 में 4.2 लाख थी। भारत का लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले 2025 तक टीबी को खत्म करना है।

पीएम नरेन्द्र मोदी ● फाइल फोटो

प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा के एक पोस्ट का जवाब देते हुए कहा, हम टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करते रहेंगे

आठ वर्षों में 17.7% तक कम हुए भारत में टीबी के मामले

स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले आठ वर्षों में भारत ने टीबी के मामलों को कम करने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 2015 से 2023 तक भारत में टीबी के मामलों में 17.7 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की है। यह वैश्विक गिरावट (8.3 प्रतिशत) के दोगुने से भी अधिक है।

ऐसे कम हुए मामले

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार टीबी के रोकथाम के लिए आवंटित बजट में ऐतिहासिक 5.3 गुना वृद्धि हुई है। 2015 में जहां 640 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे वहीं 2022-23 में इसे बढ़ाकर 3400 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके अलावा अत्याधुनिक स्वास्थ्य जांच उपकरणों, नए प्रभावशाली तरीकों को अपनाकर एवं सरकारी केंद्रों में रोगियों को मुफ्त निदान एवं उपचार की सुविधा देकर मामलों को नियंत्रित करने में सफलता मिली।

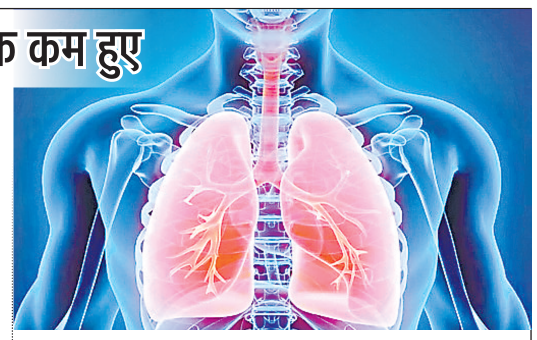

भारत में टीबी के मामले

237 मामले मिले थे टीबी के प्रति लाख आबादी पर 2015 में

195 मामले मिले टीबी के प्रति लाख आबादी पर 2023 में

25.1 लाख का निदान एवं इलाज किया गया 2023 में 27 लाख टीबी के मामलों में

28 मौतें हुई थीं 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर

22 मौतें दर्ज की गईं 2023 में प्रति लाख जनसंख्या पर

सबसे बड़ा टीबी लेबोरेटरी नेटवर्क

केंद्र सरकार टीबी के रोकथाम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीबी लेबोरेटरी नेटवर्क स्थापित करने की ओर अग्रसर है। इसके लिए 800 से अधिक एआइ से लैस पोर्टेबल चेस्ट एक्स-रे मशीनें खरीद रही है। नेटवर्क में 7,767 रैपिड टेस्टिंग सेवाओं के साथ 87 कल्चर और दवाओं के परीक्षण की सुविधा भी मौजूद होगी। (स्रोत: प्रेट्र)

डिजिटल अरेस्ट मामले में ईडी ने आठ के विरुद्ध दाखिल किया आरोप पत्र

- इस मामले में अपराध से अर्जित रकम है 159 करोड़ रुपये
- गिरफ्तार सभी आठ आरोपित इस समय न्यायिक हिरासत में

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'डिजिटल अरेस्ट' के खतरे से बचने का आग्रह किए जाने के बाद जांच एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसके तहत ही ईडी ने कर्नाटक के एक मामले में आठ लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें धोखाधड़ी की रकम लगभग 159 करोड़ रुपये है। मामले में गिरफ्तार सभी आठ आरोपित इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने एक बयान में बताया कि उसने पिछले माह बेंगलुरु की पीएमएलए अदालत में आठ आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया। जांच एजेंसी ने कहा, जांच में पाया गया कि भारत में साइबर घोटालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें फर्जी शेयर बाजार निवेश और डिजिटल अरेस्ट शामिल हैं, जिन्हें मुख्य रूप से फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्मों के जरिये अंजाम दिया जाता है। पिग बूचरिंग घोटाले के नाम से प्रचलित शेयर बाजार निवेश घोटाले में लोगों को उच्च मुनाफे का लालच देकर फर्जी वेबसाइटों व भ्रामक वाट्सएप ग्रुप्स का उपयोग करके लुभाया जाता है। ईडी ने कहा कि इस घोटाले के कुछ पीड़ितों को आरोपितों ने खुद को सीमा शुल्क और सीबीआइ का अधिकारी बताकर 'डिजिटल अरेस्ट' किया, फिर उन्हें मुखौटा कंपनियों में पैसा ट्रांसफर करने को मजबूर किया।

ईडी ने बताया कि आरोपितों ने साइबर अपराधों से प्राप्त रकम को वैध बनाने के लिए, तमिलनाडु, कर्नाटक व अन्य राज्यों में 24 मुखौटा कंपनियां बनाई थीं। ये मुखौटा कंपनियां मुख्य रूप से कोवर्किंग स्पेस (जहां कोई वास्तविक कारोबार नहीं होता) पर पंजीकृत हैं।

साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने जारी की नई एडवाइजरी

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइ4सी) ने रविवार को एक नई एडवाइजरी जारी की जिसमें लोगों से 'डिजिटल अरेस्ट' से सावधान रहने की अपील की गई है। इसमें कहा गया कि वीडियो काल करने वाले लोग पुलिस, सीबीआइ, सीमा शुल्क अधिकारी या न्यायाधीश नहीं, बल्कि साइबर अपराधी होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले संगठन ने एडवाइजरी में लोगों से इन 'चालबाजी' में नहीं फंसने और ऐसे अपराधों की शिकायत तत्काल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर या साइबर अपराधों से जुड़े आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज कराने को कहा। पीएम मोदी ने 27 अक्टूबर को रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में 'डिजिटल अरेस्ट' का मुद्दा उठाया था।

एक नजर में

छत्तीसगढ़ में ईसाई बने 11 परिवारों ने की घर वापसी

कांकेर : छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नरहरदेव शासकीय मैदान में बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र शास्त्री की उपस्थिति में रविवार को 11 ईसाई परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की। पं. शास्त्री ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और अपने धर्म पर अडिग रहने का संदेश दिया। हिंदू एकता मंच के आयोजन में श्रद्धालुओं को आत्मविश्वासी बनने के लिए पवनपुत्र हनुमान के आदर्शों व स्वामी विवेकानंद की सीख मानने को भी कहा गया। (नईदुनिया)

छग में चंगाई सभा के बहाने मतांतरण का प्रयास, केस

रायगढ़ : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चंगाई सभा की आड़ में मतांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। जूट मिल मिट्ठू मुडा इलाके में पहुंची पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। इनमें तीन महिलाएं हैं। अभाविप पदाधिकारी अंशु टूटेजा ने बताया कि यहां प्रार्थना की आड़ में मतांतरण कराया जा रहा था। हिंदू देवी-देवताओं के बारे में भ्रामक जानकारी दी जा रही थी। बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी। (नईदुनिया)

आतंकियों को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए : राशिद अल्वी

नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष डा. फारूक अब्दुल्ला के सुर में सुर मिलाते हुए रविवार को कहा कि बड़गाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को जिंदा पकड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। फारूक ने शनिवार को कहा था कि आतंकियों को मारने के बजाय उन्हें पकड़कर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए कि उनके पीछे कौन है। अल्वी ने कहा, अगर ये लश्कर के लोग हैं तो इसका साक्ष्य भी होना चाहिए। (प्रेट्र)

राजस्थान में 8.97 लाख के नकली नोटों संग युवक धरा

जोधपुर : पाकिस्तान सीमा से लगे राजस्थान के बालोतरा जिले में पुलिस ने पांच-पांच सौ के करीब 8.97 लाख के नकली नोटों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक बालोतरा के तिलवाड़ा का ही निवासी है। एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि जाली नोटों का सीरियल नंबर अलग- अलग है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को सूचित किया गया है। पूरे गिरोह को पकड़ने के लिए टीम प्रयास कर रही है। (जासं)

कोलकाता के आरजी कर कांड की जांच में मिल रहे संकेतों के आधार पर सीबीआइ सूत्रों ने कहा

महिला डाक्टर से दरिंदगी की घटना पूर्व नियोजित थी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता : सीबीआइ जांच में संकेत मिले हैं कि आरजी कर मेडिकल कालेज व अस्पताल में महिला डाक्टर से दरिंदगी की घटना पूर्व नियोजित थी। सीबीआइ सूत्रों ने बताया कि जांच में जो तथ्य मिल रहे हैं, उससे प्रतीत हो रहा है कि अस्पताल में व्याप्त आर्थिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने के डर से वारदात को अंजाम दिया गया था। आर्थिक भ्रष्टाचार के पीछे एक बड़ी साजिश है और इसमें राजनीतिक रूप से प्रभावशाली कई लोगों का हाथ होने का अनुमान है। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष व टाला थाने के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में सुबूतों को मिटाने में उनकी सक्रिय भूमिका के प्रमाण मिले हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वारदात के पूर्व नियोजित व इसके पीछे बड़ी साजिश होने का संकेत मिलने पर भी सीबीआइ की ओर से अदालत में जो चार्जशीट जमा की गई है, उसमें अस्पताल में ड्यूटी करने वाले सिविक वालंटियर संजय राय को ही एकमात्र मुख्य आरोपित बताया गया है। उससे पहले आरंभिक जांच में कोलकाता पुलिस ने भी संजय राय को एकमात्र मुख्य आरोपित बताते हुए उसे गिरफ्तार किया था। सीबीआइ मामले में संदीप घोष व अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर चुकी है। संदीप घोष को ईडी ने भी अस्पताल में आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था।

तस्वीर विकृत कर माकपा के सचिव को कहा 'दुष्कर्मी'

माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम को 'दुष्कर्मी' कहे जाने का मामला सामने आया है। सलीम ने कोलकाता पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि माकपा की ओर से आरजी कर कांड के विरुद्ध जन हस्ताक्षर अभियान चलाया था। पार्टी ने इंटरनेट मीडिया पर इसकी एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें सलीम लोगों से हस्ताक्षर संग्रह करते नजर आ रहे हैं। सलीम ने दर्ज कराई गई शिकायत में दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता पार्थ गंगोपाध्याय नामक इंटरनेट मीडिया यूजर ने विकृत किया है। तस्वीर को विकृत कर लिखा गया एक 'दुष्कर्मी' दुष्कर्म की शिकार महिला के लिए जन हस्ताक्षर संग्रह कर रहा है। सलीम ने कहा,उनके सम्मान को हानि पहुंची है।

बंगाल में फिर हैवानियत, ट्यूशन से घर लौट रही छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में गाइघाटा इलाके में छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपित के परिवार का राज्य में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस से संबंध है। मालूम हो कि पिछले 24 घंटे में राज्य में नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की यह तीसरी घटना है। इससे पहले अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम और मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल में ऐसी घटना हुई थीं। गाइघाटा से भाजपा विधायक सुब्रत ठाकुर ने आरोपित के परिवार व स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं पर पीड़ित परिवार को धमकाने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ स्थानीय तृणमूल नेता प्रसेनजीत घोष ने आरोप से इन्कार करते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा।

पीड़िता के माता-पिता की ओर से थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार शुक्रवार शाम को उनकी बेटी ट्यूशन से घर लौट रही थी। उसी वक्त उसका अपहरण कर उसे सुनसान जगह ले जाया गया, जहां आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने घर लौटने के बाद कुछ नहीं बताया। शनिवार शाम उसने आत्महत्या की कोशिश की। जोर देकर पूछने पर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने शनिवार देर रात आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपित के खिलाफ पहले भी छेड़छाड़ की शिकायतें मिलती रही हैं। एक साल पहले भी इसी पीड़िता ने उसके विरुद्ध छेड़छाड़ की शिकायत की थी।

तृणमूल विधायक बोले- 'बाहरी लोगों' के कारण बंगाल में बढ़ रहे दुष्कर्म

तृणमूल कांग्रेस विधायक मनोरंजन ने राज्य में दुष्कर्म व हत्या की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए इसके लिए 'बाहरी लोगों' को जिम्मेदार ठहराया है। विधायक का इशारा बंगाल में रह रहे बिहार- यूपी व अन्य राज्यों के लोगों की तरफ बताया जा रहा है। हुगली जिले के बालागढ़ से तृणमूल विधायक ने फेसबुक पर चिंता जताते हुए लिखा- 'बंगाल में पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। क्या बंगाल दुष्कर्मियों और हत्यारों के लिए उत्सव स्थल बन गया है? उनमें (अपराधियों में) इतनी हिम्मत कैसे आ रही है? वे बार-बार शांत स्थलों पर अशांति की आग सुलगा रहे हैं।'

बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं : राज्यपाल

राज्यपाल डा सीवी आनंद बोस ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए ममता सरकार की आलोचना की। भाई दूज के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा- 'पिछले साल जब मैं संदेशखाली गया था तो वहां की बहनों ने कहा था कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आरजी कर कांड के बाद अब मुझे भी लगता है कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है इसलिए मैंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'अभया प्लस' नामक आत्मरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है।

सीवी आनंद बोस फाइल फोटो

बुलंदशहर में वंदे भारत ट्रेन पर फेंका पत्थर, खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता. बुलंदशहर : दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर रविवार सुबह कमालपुर और डांबर स्टेशन के बीच किसी ने पत्थर फेंक दिया। इससे एक कोच की खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त गुलजार सिंह ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

खुर्जा जंक्शन से आगे कमालपुर व डांबर स्टेशन के बीच वंदेभारत एक्सप्रेस के कोच संख्या सी-3 सीट नंबर 53, 54 की खिड़की का कांच पत्थर लगने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि ट्रेन को रोका नहीं गया। इसी कोच में यात्रा कर रहे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट कर घटना की निंदा की है। वह दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री, रेलवे पुलिस व प्रशासन से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। आरपीएफ प्रभारी नंदलाल मीणा, अरनिया थाना पुलिस एवं जीआरपी ने इस बारे में जानकारी जुटाई है।

दैनिक जागरण नई राहें एक नई शुरुआत

रोटरी विंग अनुसंधान व अभिकल्प केंद्र
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
एचएएल के साथ बुलंदियों को छूएँ
बेंगलूरु - 560017

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), एक महारत्न, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख वैमानिकी उद्योग है। एचएएल के देशभर में 20 उत्पादन/ ओवरहाल प्रभाग, 9 सह-स्थित अनुसंधान एवं विकास केंद्र तथा 1 सुविधा प्रबंधन प्रभाग है।

एचएएल, प्रभागों/ आरसीएमए (क्षेत्रीय सैन्य उड़न-योग्यता केंद्र) / सेमिलाक (सैन्य उड़न-योग्यता और प्रमाणन केंद्र), डीआरडीओ, बेंगलूरु की प्रयोगशाला में तैनाती हेतु अल्पकालिक आधार पर (2 वर्ष की अवधि के लिए, आवश्यकतानुसार एक और वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।) कार्यपालक संवर्ग में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है :

क्र सं	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	आरक्षण
01	सीएमएम (लेवेल-5) इंजीनियर	04	03- यूआर, 01-ओबीसी (एनसीएल)
02	मिडल स्पेशालिस्ट	12	11- यूआर, 01-ओबीसी (एनसीएल)
03	जूनियर स्पेशलिस्ट	8	06- यूआर, 02-ओबीसी (एनसीएल)

विस्तृत विज्ञापन एचएएल वेबसाइट www.hal-india.co.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए एचएएल वेबसाइट देख सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन में दिए गए अनुदेशों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में अपने विधिवत भरे हुए आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 29.11.2024 है। शुद्धिपत्र/ परिशिष्ट, यदि कोई होगा, तो उसे एचएएल की वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जाएगा।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
(रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उपक्रम)
एवियानिक्स प्रभाग :: हैदराबाद

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) एक महारत्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम है जो दक्षिण पूर्वी एशिया का अग्रगामी वांतरिक्ष उद्योग है। इसके देशभर में व्याप्त 21 उत्पादन/ ओवरहॉल, सेवा प्रभाग, 9 अनुसंधान एवं अभिकल्प केन्द्र तथा 1 सुविधा प्रबंधन प्रभाग हैं।

एच ए एल, हैदराबाद द्वारा कार्यपालक वर्ग में अल्पकालिक आधार पर निम्नलिखित पदों के लिए कर्मियों की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है:

सीएमएम (स्तर-5) अभियंता - 4 पद
मध्य स्तरीय विशेषज्ञ - 8 पद
कनिष्ठ विशेषज्ञ - 5 पद

आरक्षण, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आवश्यकताओं, छूट, आवेदन के माध्यम, चयन पद्धति, भर्ती स्थान आदि से संबंधित विवरण के लिए कृपया एचएएल वेबसाइट www.hal-india.co.in देखें। आवेदन की अंतिम तिथि 24.11.2024 है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)
(CIN: L32309KA1954GOI000787)

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी तथा भारत की अग्रणी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बेंगलूरु संकुल के लिए प्रबंधक(ई-V)पद हेतु तुरंत भर्ती/पुनः नियोजन के आधार पर सेवारत/सेवा निवृत नौसेना अधिकारियों की आवश्यकता है।

पद/ग्रेड	पदों की संख्या	पात्रता मानदंड और अनुभव 01.10.2024	योग्यता	वेतनमान
प्रबंधक (ई-V)	अनारक्षित-02 अ.पि.व.-01 कुल-03	कमांडर/लेप्टिनेंट कमांडर की श्रेणी में 4 वर्षों की वरिष्ठता। न्युनतम 12 वर्षों का संगत अनुभव	इलेक्ट्रॉनिक्स / कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रिकल में बीई / बीटेक में उत्तीर्ण श्रेणी	रु.70,000 -3%- 2,00,000

आवेदन करने की अंतिम दिनांक 20.11.2024 है। आवेदन से संबंधी विस्तृत व विरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.bel-india.in के 'CAREERS' लिंक को देखें।
ह /-
दिनांक: 30.10.2024 प्रबंधक – मा सं (एन एस – एस एंड सी एस)
'हर एक काम देश के नाम'

हरियाणा के निकाय चुनाव में नहीं मिलेगा अन्य राज्य की एससी महिला को आरक्षण

सुधीर तंवर ● जागरण

चंडीगढ़ : हरियाणा में सामान्य वर्ग के पुरुष से शादी करने वाली दूसरे राज्यों की अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की महिलाओं को स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि हरियाणा की ऐसी महिलाएं प्रभावित नहीं होंगी। दूसरे प्रदेशों द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र के सहारे प्रदेश में आरक्षित सीटों पर निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल, कई उपायुक्तों ने आयोग से पूछा था कि क्या किसी अन्य राज्य का अनुसूचित जाति का व्यक्ति स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण का लाभ ले सकता है? आयोग ने विधि एवं विधायी विभाग से स्पष्टीकरण मांगा था कि यदि हरियाणा से संबंधित आरक्षित या अनारक्षित श्रेणी का कोई पुरुष अन्य राज्य की अनुसूचित जाति की महिला से विवाह करता है और वह जाति हरियाणा में अनुसूचित जातियों की सूची में भी शामिल है तो क्या महिला स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण का लाभ ले सकती है? यदि हां तो क्या अन्य राज्य द्वारा जारी प्रमाणपत्र वैध माना जाएगा?

आइएनएस विक्रांत धोखाधड़ी में किरीट सोमैया को फिर से मिली क्लीन चिट

फैजान खान ● मिडडे

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 57 करोड़ रुपये की आइएनएस विक्रांत धोखाधड़ी मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को क्लीनचिट देते हुए दूसरी बार क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। सोमैया पर आरोप है कि उन्होंने सेवामुक्त विमानवाहक पोत के संरक्षण के लिए जनता से दान एकत्र किया, लेकिन वह धनराशि महाराष्ट्र सरकार या राज्यपाल को ट्रांसफर नहीं की।

दूसरी क्लोजर रिपोर्ट में ईओडब्ल्यू ने कहा कि उसे कथित 57 करोड़ रुपये के लेन-देन का कोई साक्ष्य नहीं मिला। हालांकि, इसने 12,881 की छोटी राशि का पता लगाया, जिसे किरीट सोमैया ने कथित तौर पर 10 दिसंबर, 2013 को चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास आयोजित दान अभियान के दौरान एकत्र किया था। इस कार्यक्रम के बाद सोमैया ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन से मुलाकात कर एकत्रित राशि उन्हें सौंप दी।

ईओडब्ल्यू रिपोर्ट में राजभवन के अधिकारियों के बयान शामिल हैं, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि बैठक हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि सोमैया ने कितनी राशि सौंपी, इसका कोई रिकार्ड नहीं है। चूंकि शंकरनारायणन का निधन हो चुका है, इसलिए विवरणों की पुष्टि करना चुनौतीपूर्ण है। ईओडब्ल्यू ने कहा कि सोमैया के नेतृत्व में चर्चगेट दान अभियान का उद्देश्य 1997 में सेवामुक्त आइएनएस विक्रांत के बारे में जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना था।

किरीट सोमैया ● फाइल फोटो

लाल सागर में संकट से भारत में हुई डीएपी की किल्लत

- जरूरत का मात्र 40 प्रतिशत होता है घरेलू उत्पादन
- शेष डीएपी के लिए देश की आयात पर है निर्भरता

55.67 लाख टन डीएपी का 2023-24 में हुआ था आयात

42.93 लाख टन था पिछले वर्ष डीएपी का घरेलू उत्पादन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गेहूं समेत रबी फसलों की बोआई का मौसम चल रहा है, लेकिन लाल सागर में संकट की वजह से किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट डीएपी का है। देश को प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के लिए 90 से सौ लाख टन डीएपी की जरूरत पड़ती है, जिसका करीब 40 प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा होता है। बाकी के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस वर्ष भी देश में लगभग 93 लाख डीएपी की जरूरत बताई गई है, लेकिन घरेलू उत्पादन एवं आयात दोनों को मिलाकर उपलब्धता लगभग 75 लाख टन डीएपी की है। संकट दिख रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उर्वरकों की कमी नहीं होने दी जाएगी। तरल संस्करण नैनो डीएपी के भी इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है।

डीएपी संकट के बारे में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर ज्यादा है। मुख्य रूप से रूस, जार्डन एवं इजरायल से आयात करना पड़ता है। डीएपी के कच्चे माल के रूप में म्यूरेट आफ पोटाश (एमओपी) का आयात जार्डन से करीब 30 प्रतिशत और इजरायल से 15 प्रतिशत होता है। हाल के दिनों में हाउती विद्रोहियों के आक्रमण के चलते लाल सागर का मार्ग अवरुद्ध होने से उर्वरक के जहाजों को दक्षिण अफ्रीका के रास्ते भेजना पड़ रहा है। इसके चलते पहले की तुलना में लगभग 6,500 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करनी पड़ रही है। इसमें लगभग तीन सप्ताह का समय ज्यादा लग रहा है। इससे उर्वरकों की आयात लागत बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय मूल्य भी बढ़े हैं। हालांकि तमाम चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार उर्वरकों की उपलब्धता जारी रखते हुए कीमतों को भी स्थिर बनाए हुए है। किसानों को प्रत्येक 50 किलो डीएपी बैग के लिए 1,350 रुपये देने पड़ते हैं।

2019-2020 में 48.70 लाख टन डीएपी का आयात हुआ था, जो 2023-24 में बढ़कर 55.67 लाख टन तक पहुंच गया। इसी तरह 2023-24 में में डीएपी का घरेलू उत्पादन मात्र 42.93 लाख टन था।

पंजाब-हरियाणा से ज्यादा मांग : डीएपी की ज्यादा मांग पंजाब एवं हरियाणा से आ रही है, जहां रबी फसलों की बुआई प्रारंभ हो चुकी है। बाकी राज्यों में अभी धान की फसलें पूरी तरह नहीं कटी हैं। मध्य नवंबर और दिसंबर से अन्य राज्यों में भी मांग बढ़ने वाली है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने दावा किया है कि खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। पंजाब में डीएपी की कमी के आरोपों को खारिज करते हुए ब्योरा भी दिया है कि केंद्र ने अक्टूबर में पंजाब को 92 हजार टन डीएपी एवं 18 हजार टन एनपीके की आपूर्ति की है। नवंबर के पहले हफ्ते में भी केंद्र द्वारा 50 हजार टन डीएपी पंजाब को भेजा जाना है। हरियाणा का भी ऐसा ही हाल है। केंद्र की रिपोर्ट बताती है कि सितंबर में हरियाणा की ओर से 60 हजार टन डीएपी की मांग आई थी। मगर केंद्र की तरफ से 64 हजार 708 टन डीएपी की आपूर्ति की गई, जो मांग से ज्यादा है।

पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका, चार झुलसे

- सामान्य डिब्बे में बाल्टी में रखे पटाखों में हुआ विस्फोट
- त्योहारों पर घर जा रहे थे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब : पंजाब में सरहिंद रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात्रि अमृतसर-हावड़ा मेल (13006) के जनरल कोच में धमाका हो गया। भीड़ व सामान से खचाखच भरे कोच में धुआं भरने से अफरातफरी मच गई। धमाके के कारण एक महिला सहित चार यात्री झुलस गए। जान बचाने के लिए बीस से अधिक यात्री चलती ट्रेन से कूद गए। ट्रेन की रफ्तार कम होने के कारण कोई घायल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि विस्फोट एक यात्री के सामान में बाल्टी में रखे पटाखों से हुआ।

घायल यात्रियों की पहचान बिहार के भोजपुर पीरू निवासी अजय कुमार व उसकी पत्नी संगीता कुमारी, उप्र के बहराइच निवासी आशुतोष पाल और बिहारा के नवादा बाजार के सोनू कुमार के रूप में हुई है। आशुतोष पाल के भाई राकेश ने बताया कि वे लोग अमृतसर से हावड़ा मेल में बैठे थे। ट्रेन ने अभी सरहिंद रेलवे स्टेशन आगे बढ़ी ही थी कि रात 10.30 बजे अचानक जोर का धमाका हुआ। उस समय अधिकतर सवारियां सो रहीं थीं। धमाका सुनकर चीख-पुकार मच गई। डरकर यात्रियों ने ट्रेन से बाहर कूदना शुरू कर दिया। ट्रेन की रफ्तार कम होने से नीचे कूदे यात्रियों को गंभीर चोटें नहीं आईं।

कोच में सफर कर रहे यात्रियों ने बताया कि फगवाड़ा के पास दो सुरक्षाकर्मी चेकिंग के लिए आए थे। सुरक्षा कर्मियों ने कुछ यात्रियों की जेबें टटोलीं, कुछ के सामान को डंडे से ठोंका और कुछ लोगों की जेब से तंबाकू बरामद करने के बाद उनसे पैसे ऐंठकर चलते बने।

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्च शिक्षा विभाग
तकनीकी अनुभाग- I

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड (आईआईआईटी-पीपीपी) में स्थापित नागपुर, श्री सिटी (चित्तूर), कोटा, लखनऊ, कोट्टायम, तिरुचिरापल्ली और गुवाहाटी के निदेशक पद के लिए विज्ञापन

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड (आईआईआईटी- पीपीपी) में स्थापित **नागपुर, श्री सिटी (चित्तूर), कोटा, लखनऊ, कोट्टायम, तिरुचिरापल्ली और गुवाहाटी** के निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आईआईआईटी के निदेशक, अकादमिक और प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का नेतृत्व करने के लिए नेतृत्व गुणों के साथ प्रशासनिक, शिक्षण और अनुसंधान पृष्ठभूमि (पीएचडी स्तर पर अनुसंधान मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण अनुभव सहित) की अपेक्षा की जाती है। उम्मीदवार को उचित शाखा में पीएचडी होना चाहिए, साथ ही पूरे शैक्षणिक रिकॉर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन और एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में प्रोफेसर के रूप में **कम से कम 7 साल का अनुभव** होना चाहिए (उत्कृष्ट उम्मीदवार के मामले में छूट दी जा सकती है)। आवेदक की आयु अधिमानत : 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस पद पर 7 वें सीपीसी के अनुसार 2,10,000 /- रुपये (निर्धारित) का निश्चित वेतन और 11,250 रुपये प्रति माह का विशेष भत्ता जिसमें संस्थान के नियमों के तहत स्वीकार्य भत्ते शामिल हैं।

योग्य/इच्छुक व्यक्ति NITSER काउंसिल की वेबसाइट : **www.nitcouncil.org.in** और शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट : **http://www.education.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन विंडो **04.11.2024 से 03.12.2024 रात्रि 11:59 बजे** तक खुली रहेगी। दोनों तिथियां शामिल हैं।

यदि अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच कोई असंगतता या अस्पष्टता है, तो अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।

अन्य आवश्यक जानकारी के साथ विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट **http://www.education.gov.in, www.nitcouncil.org.in**, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की वेबसाइट : **http://www.dst.gov.in/** और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट : **https://dopt.gov.in/** पर दिए गए हैं।